

फेम-2 योजना

संदर्भ

- नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (आरएमआई) विद्युत चालित वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण-2 (फेम 2) योजना के तहत वाहन क्षेत्र और सरकार के लिए अवसरों पर एक रिपोर्ट जारी की गई।
- शीर्षक 'भारत के विद्युत चालित वाहन क्षेत्र में बदलाव: प्रगति और भविष्य में अवसर'

उद्देश्य-

- इसका उद्देश्य भविष्य में स्वच्छ वाहन क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र में विद्युतीकरण को बढ़ावा देना है। फेम-2 लक्ष्य कुशल आर्थिक विकास और भारत के वाहन उद्योग के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने के लिए विद्युत चालित वाहनों को तेजी से स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु-

- विद्युत वाहनों की स्वीकार्यता को आसान बनाने के लिए भारत के वाहन उद्योग की सक्रिय भागीदारी की जरूरत है। वाहन और बैटरी उद्योग ईवी को प्रोत्साहन देने के लिए ग्राहकों की जागरूकता को बढ़ावा देना, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन, नए बिजनेस मॉडल पर विचार कर सकते हैं।
- सरकार को ईवी (EV) को प्रोत्साहन देने के लिए ईवी (EV) और बैटरियों के विनिर्माण के वास्ते एक चरणबद्ध विनिर्माण योजना, वित्तीय प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विभिन्न सरकारी विभागों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए संभावित नीतियों, कम उत्सर्जन/निषेध क्षेत्रों, पार्किंग नीतियों आदि पर विचार करना चाहिए।
- विद्युत वाहन बाजार फेम-2 जैसी नीतियों और वाहन उद्योग के लिए देश के नागरिकों को नए मोबिलिटी सॉल्यूशन उपलब्ध करायेगा। इस तरह के बदलाव से भारत के नागरिकों के लिए व्यापक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण लाभ उपलब्ध हो पायेंगे।
- रिपोर्ट में फेम-2 के अंतर्गत प्रोत्साहन हासिल करने वाले वाहनों से होने वाली तेल और कार्बन की बचत का आकलन किया गया।
- रिपोर्ट में उस प्रेरक प्रभाव का आकलन भी किया गया, जो फेम-2 और अन्य उपायों की वजह से पूरे विद्युत वाहन (ईवी) बाजार पर पड़ सकता है।
- विश्लेषण के अनुसार** - यदि फेम-2 और अन्य उपाय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में सफल होते हैं तो भारत में वर्ष 2030 तक ईवी की बिक्री कुल कारों की बिक्री की 30 प्रतिशत, वाणिज्यिक वाहनों की 70 प्रतिशत, बसों में 40 प्रतिशत और दोपहिया व तीन पहिया वाहनों में 80 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच सकती है।
- इसके विस्तार से फेम-2 से होने वाली प्रत्यक्ष बचत की तुलना में विद्युत चालित वाहनों से जीवन भर में तेल और कार्बन की बचत कई गुना ज्यादा हो सकती है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2030 तक बाजार हिस्सेदारी के इस स्तर को हासिल करके 846 मिलियन टन कार्बन की बचत हो सकती है।
- फेम 2 के दायरे में आने वाले दो, तीन, चार पहिया वाहनों और बसों से बड़ी मात्रा में ऊर्जा और CO2 की बचत होगी।
- वर्ष 2030 तक संभावित अवसरों को भुनाने के क्रम में बैटरियों पर भी ज्यादा जोर होना चाहिए, क्योंकि विद्युत चालित वाहनों की लागत के लिहाज से इनका योगदान खासा ज्यादा होगा।
- फेम 2 योजना के तहत पात्र वाहनों से जीवन पर्यंत 5.4 मिलियन टन तेल की बचत हो सकती है, जिसका मूल्य 17.2 हजार करोड़ रुपये होगा।
- वर्ष 2030 तक बिकने वाले विद्युत चालित वाहन से कुल 474 मिलियन टन के बराबर तेल की बचत हो सकती है, जिसकी कुल लागत लगभग 15 लाख करोड़ रुपये होगी। इससे ईवी के जीवनकाल के दौरान कुल 846 मिलियन टन सीओ2 की बचत होगी।

हर तीन किमी की दूरी पर बनाए जाएंगे चार्जिंग स्टेशन

- योजना के तहत 7 हजार बसों, 55 हजार कारों, 5 लाख तिपहिया और 10 लाख दोपहिया पर सब्सिडी देने की योजना

है। यह सब्सिडी उन्हीं वाहनों के लिए दी जाएगी जिनमें लिथियम ऑयन या दूसरी नई टेक्नोलॉजी की बैटरी होगी। इन वाहनों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया जाएगा। शहरों में हर तीन किमी की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। हाईवे पर हर 25 किमी पर चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। फेम-1 योजना अप्रैल 2015 में लागू हुई थी। इसके तहत 895 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।

फेम-स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल के अनुकूल इन्फ्रास्ट्रक्चर का भी विकास किया जाएगा। इसके तहत देशभर में 2,700 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन' लगाने का प्रावधान है।

कैसे तय होगी सब्सिडी?

यह सब्सिडी अप्रैल से प्रभावी होगी। इस योजना के तहत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के एक्स फैक्ट्री प्राइस पर भी कैप लगा सकती है। वह इसे 15 लाख रुपए पर सीमित कर सकती है। किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी उसकी बैटरी कैपेसिटी के आधार पर तय होती है यानि वाहनों पर 10 हजार रुपए प्रति KWH और घरों पर 20 हजार KWH।

क्या होगा फायदा?

सब्सिडी लागू होने पर ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इससे न सिर्फ उनकी ईंधन लागत घटेगी बल्कि कार की कीमत पर भी असर पड़ेगा। इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ने से पेट्रोल पंप की तरह जगह-जगह इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे वहीं पेट्रोल की खपत भी कम होगी।

भारत सरकार की फेम-2 (फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) स्कीम 1 अप्रैल 2019 से देश में लागू होने वाली है। फेम-2 स्कीम के तहत 10,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिससे विभिन्न मोटर वाहन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक कार, हाइब्रिड कार, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और ई-रिक्शा शामिल है।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

1. फेम-2 योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
 1. इस योजना के अंतर्गत डीजल व पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जायेगा।
 2. इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी नीति आयोग है।
 उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?
 - (a) केवल 1
 - (b) केवल 2
 - (c) 1 और 2 दोनों
 - (d) इनमें से कोई नहीं

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न- जलवायु परिवर्तन व वायु प्रदूषण में परिवहन के साधनों का योगदान अधिक रहता है। इस संबंध में फेम-1 फेम-2 जैसी योजनाएं किस हद तक इस समस्या पर नियंत्रण लगा सकती है? चर्चा करें।